RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 241
दि. 01.01.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

नाइमेसुलाइड की ऊंची डोज पर सख्ती, 100 मिलीग्राम से ज्यादा वाली दर्द निवारक दवाओं पर केंद्र का त्वरित प्रतिबंध

नई दिल्ली। बुखार और दर्द में तेजी से राहत देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नाइमेसुलाइड दवा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली नाइमेसुलाइड की सभी ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर देशभर में तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत लागू किया गया है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि अधिक डोज वाली नाइमेसुलाइड मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है, खासतौर पर लिवर पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव सामने आए हैं, जबकि कम डोज और अन्य सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली नाइमेसुलाइड दवाएं इंसानों के लिए संभावित रूप से खतरनाक हो सकती हैं। नाइमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग यानी एनएसएआईडी है, जिसका इस्तेमाल बुखार, दर्द और सूजन में किया जाता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा से लिवर टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है। मंत्रालय के अनुसार, इस दवा के सुरक्षित उपयोग को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं और देश-दुनिया में इसके दुष्प्रभावों पर लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेने के बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।

अधिसूचना में साफ किया गया है कि यह प्रतिबंध केवल 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाले तुरंत रिलीज होने वाले ओरल फॉर्मूलेशन पर लागू होगा। कम डोज वाली नाइमेसुलाइड और अन्य वैकल्पिक दर्द निवारक दवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी। सरकार ने कहा है कि जनहित में यह फैसला जरूरी था ताकि आम लोगों को ऐसी दवाओं से होने वाले संभावित नुकसान से बचाया जा सके। मंत्रालय का मानना है कि जब सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं, तो अधिक जोखिम वाली दवाओं को बाजार में बनाए रखना उचित नहीं है।

नाइमेसुलाइड को लेकर यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने सख्ती दिखाई हो। साल 2011 में 12 साल से कम उम्र के बच्चों में नाइमेसुलाइड के इस्तेमाल पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है, क्योंकि बच्चों में इसके दुष्प्रभाव का खतरा अधिक पाया गया था। इसके बाद जनवरी 2025 में सरकार ने पशुओं के लिए नाइमेसुलाइड की सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि यह दवा पशुओं के जरिए पर्यावरण और जैव विविधता के लिए भी खतरनाक साबित हो रही थी। अब इंसानों के लिए ऊंची डोज पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि दवा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बाजार से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में नाइमेसुलाइड दवाओं का कुल बाजार करीब 497 करोड़ रुपये का है और पिछले 12 महीनों में इसमें लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आंकड़े मार्केट रिसर्च फर्म फार्माट्रैक के हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि 100 मिलीग्राम से अधिक डोज पर प्रतिबंध से दवा बाजार पर बड़ा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि एनएसएआईडी श्रेणी में कई अन्य विकल्प मौजूद हैं। फिर भी, जिन कंपनियों का कारोबार मुख्य रूप से नाइमेसुलाइड पर निर्भर है, खासकर छोटी फार्मा कंपनियां, उन्हें इस फैसले से आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

फार्मा सेक्टर से जुड़े जानकारों के अनुसार, नाइमेसुलाइड ब्रांड की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों को अब तत्काल उत्पादन रोकना होगा और बाजार में मौजूद प्रभावित बैचों को वापस मंगाना पड़ेगा। बड़ी फार्मा कंपनियों पर इसका असर सीमित रहने की उम्मीद है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में कई अन्य दवाएं शामिल हैं, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए यह फैसला चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार इससे पहले भी सेक्शन 26A के तहत कई हाई-रिस्क दवाओं और फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा चुकी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य में भी दवा सुरक्षा मानकों को और सख्त किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, नाइमेसुलाइड की ऊंची डोज पर लगाया गया यह प्रतिबंध सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जिसमें मरीजों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है। तेजी से राहत देने वाली दवाओं के साथ जुड़े जोखिमों को देखते हुए सरकार अब धीरे-धीरे अधिक खतरे वाली दवाओं को बाहर करने और सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि इलाज के नाम पर किसी की सेहत से खिलवाड़ न हो।

भारत की सामरिक शक्ति को नई धार, एक ही लॉन्चर से दो 'प्रलय' मिसाइलों का सफल परीक्षण

नई दिल्ली। भारत की स्वदेशी मिसाइल क्षमता ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए सामरिक ताकत के मोर्चे पर नई मजबूती दिखाई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एक ही लॉन्चर से लगातार दो 'प्रलय' मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल के तहत किया गया, जिसमें दोनों मिसाइलों ने निर्धारित लक्ष्य, तय उड़ान पथ और सभी तकनीकी मानकों को पूरी तरह पूरा किया। इस सफलता को भारत की पारंपरिक युद्ध क्षमता को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को सुबह लगभग 10.30 बजे समुद्र तट से यह परीक्षण किया गया। खास बात यह रही कि दोनों मिसाइलें एक ही लॉन्चर से बैक-टु-बैक दागी गईं, जिससे सिस्टम की त्वरित प्रतिक्रिया और ऑपरेशनल रेडीनेस का सफल प्रदर्शन हुआ। चांदीपुर टेस्ट रेंज पर तैनात आधुनिक ट्रैकिंग सेंसर और रडार सिस्टम ने पुष्टि की कि मिसाइलों ने अपने तय रास्ते का सटीक रूप से पालन किया। वहीं, लक्ष्य क्षेत्र के पास तैनात जहाज पर लगे टेलीमेट्री सिस्टम ने अंतिम चरण की सभी घटनाओं को रिकॉर्ड कर लिया, जिससे परीक्षण की सफलता पर अंतिम मुहर लगी।

प्रलय मिसाइल को भारत की पारंपरिक युद्ध रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। यह एक शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी अत्यधिक गति और मारक सटीकता है। बताया जाता है कि यह मिसाइल करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य की ओर बढ़ सकती है और 500 से 1000 किलोग्राम तक का पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इतनी अधिक गति और भारी पेलोड के कारण यह दुश्मन के अहम सैन्य ठिकानों के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि प्रलय मिसाइल को विशेष रूप से रडार इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एयरस्ट्रिप और अन्य रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस्ड इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का समर्थन मिलता है। यह तकनीक मिसाइल को उड़ान के दौरान अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देती और अंतिम क्षणों में भी उच्च स्तर की सटीकता सुनिश्चित करती है। इसी कारण इसे हाई-प्रिसिशन स्ट्राइक हथियार माना जा रहा है।

एक ही लॉन्चर से दो मिसाइलों का लगातार परीक्षण इस बात का संकेत है कि भारतीय सेना भविष्य में तेजी से जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम होगी। जरूरत पड़ने पर कम समय में कई लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे दुश्मन की रक्षा प्रणाली पर भारी दबाव पड़ेगा। सामरिक विश्लेषकों के मुताबिक, प्रलय मिसाइल की तैनाती से पाकिस्तान के कई प्रमुख सैन्य और शहरी ठिकाने इसकी जद में आ सकते हैं, जिससे भारत की पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी।

यह परीक्षण 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रलय मिसाइल न केवल आयातित हथियार प्रणालियों पर निर्भरता कम करती है, बल्कि देश के रक्षा उद्योग को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाती है।

बंगाल की सियासत में 2026 की बिसात अमित शाह ने साधा एकजुटता का दांव

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कोलकाता में भाजपा की राज्य इकाई के शीर्ष नेताओं, सांसदों, विधायकों और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक कर न सिर्फ तैयारियों की समीक्षा की, बल्कि पार्टी के भीतर एकजुटता का स्पष्ट संदेश भी दिया। इस कवायद का सबसे अहम संकेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को फिर से प्रमुख चुनावी चेहरों में आगे लाना माना जा रहा है, जिससे पार्टी पुराने और नए नेतृत्व के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है।

बैठक में अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि 2026 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि संगठन की परीक्षा का भी चुनाव होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को जनता के बीच लगातार मौजूद रहने का निर्देश देते हुए कहा कि अगले कुछ महीने निर्णायक होंगे। शाह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, जो जमीनी स्तर पर सक्रियता और प्रभाव साबित करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, शाह ने यह संदेश भी दिया कि संगठन में किसी भी तरह की गुटबाजी या निष्क्रियता को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस बैठक का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया, क्योंकि इसमें दिलीप घोष को एक बार फिर केंद्रीय भूमिका में लाने का संकेत दिया गया। पार्टी के भीतर लंबे समय से यह चर्चा थी कि पुराने और नए नेतृत्व के बीच समन्वय की कमी भाजपा की कमजोरी बन रही है। शाह की मौजूदगी में दिलीप घोष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की साझा मौजूदगी को इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। इसे 2026 से पहले मतभेद कम करने और एक साझा रणनीति पर सहमति बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

पार्टी नेताओं के अनुसार, अमित शाह ने बैठक में जनसंपर्क को सबसे बड़ा हथियार बताते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा को गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचना होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में अधिकांश समय अपने-अपने क्षेत्रों में बिताने और नियमित जनसंवाद करने की सलाह दी। शाह ने यह भी संकेत दिया कि आक्रामक लेकिन संगठित प्रचार ही तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ को चुनौती दे सकता है। यही वजह है कि दिलीप घोष की तेजतर्रार और आक्रामक शैली को एक बार फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाने की तैयारी दिख रही है। बैठक के बाद दिलीप घोष के बयानों से भी यह साफ हो गया कि वे 2026 के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भाजपा के भीतर उन्हें वह नेता माना जाता है, जिन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर खड़ा किया और पार्टी को बंगाल में मुख्य विपक्षी ताकत बनाया। उनके कार्यकाल में भाजपा ने विधानसभा में ऐतिहासिक बढ़त हासिल की और लोकसभा चुनाव में भी अभूतपूर्व सफलता दर्ज की थी। ऐसे में पार्टी नेतृत्व मानता है कि घोष का अनुभव और जनाधार आने वाले चुनाव में बड़ा हथियार बन सकता है। राजनीतिक बैठकों के अलावा अमित शाह ने कोलकाता प्रवास के दौरान धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद उन्होंने मध्य कोलकाता स्थित थंथानिया काली मंदिर में पूजा-अर्चना की।

इसे बंगाल की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं से जुड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, शाह के दौरे के दौरान सियासी माहौल भी गरमाया रहा। कॉलेज स्ट्रीट इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी।

कुल मिलाकर अमित शाह का यह दौरा भाजपा के लिए संगठनात्मक मजबूती, नेतृत्व के बीच तालमेल और चुनावी आक्रामकता—तीनों मोर्चों पर अहम माना जा रहा है। 2026 की लड़ाई को देखते हुए भाजपा अब स्पष्ट रूप से पुराने अनुभव और नए नेतृत्व को एक मंच पर लाकर बंगाल की सियासत में बड़ी चुनौती देने की रणनीति पर काम करती नजर आ रही है।

ऊर्जा बचत की दिशा में बड़ा कदम, टीवी से लेकर एलपीजी चूल्हे तक पर अब अनिवार्य होगी स्टार रेटिंग

नई दिल्ली। ऊर्जा संरक्षण और बिजली की खपत को नियंत्रित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए एक जनवरी से कई घरेलू और औद्योगिक उपकरणों पर ऊर्जा दक्षता वाली स्टार रेटिंग को अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस निर्णय के तहत अब रेफ्रिजरेटर, टीवी, एलपीजी गैस चूल्हा और कूलिंग टॉवर जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बिना स्टार रेटिंग के बाजार में नहीं बेचे जा सकेंगे। बिजली मंत्रालय के अधीन कार्यरत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, इस नियम का दायरा और भी बढ़ाया गया है, जिसमें डीप फ्रीजर, वितरण ट्रांसफॉर्मर और ग्रिड से जुड़े सोलर इनवर्टर भी शामिल किए गए हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को ऊर्जा की खपत के प्रति जागरूक बनाएगा, बल्कि देशभर में बिजली की बचत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीईई की स्टार रेटिंग प्रणाली लंबे समय से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने का एक प्रमुख साधन रही है। इसके तहत किसी भी उपकरण को उसकी बिजली खपत और कार्यक्षमता के आधार पर एक से पांच स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। अधिक स्टार का अर्थ है कम बिजली खपत और बेहतर ऊर्जा दक्षता, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भी सीधी बचत होती है। अब तक कई उपकरणों पर स्टार रेटिंग केवल स्वैच्छिक थी। फ्रॉस्ट-फ्री और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, डीप रेफ्रिजरेटर, विभिन्न प्रकार के एयर कंडीशनर जैसे कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टावर, सीलिंग और कॉर्नर एसी, साथ ही रंगीन टीवी और अल्ट्रा एचडी टीवी पर ऊर्जा रेटिंग दिखाना अनिवार्य नहीं था। इसके चलते उपभोक्ताओं के लिए यह समझना कठिन हो जाता था कि कौन सा उपकरण ज्यादा बिजली खपत करेगा और कौन सा ऊर्जा की बचत में मददगार है। नए नियम के लागू होने से अब खरीदारी के समय उपभोक्ता के पास स्पष्ट जानकारी होगी, जिससे वे सोच-समझकर फैसला ले सकेंगे। हालांकि, इससे पहले भी सरकार कुछ प्रमुख उपकरणों पर स्टार रेटिंग को अनिवार्य कर चुकी है। रूम एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर, वाशिंग मशीन, ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप और सेल्फ-बैलास्टेड एलईडी लैंप जैसे उत्पादों पर पहले से ही ऊर्जा रेटिंग लागू है। इन अनुभवों के आधार पर सरकार का मानना है कि अनिवार्य स्टार रेटिंग से बाजार में ऊर्जा दक्ष उत्पादों की मांग बढ़ती है और निर्माता कंपनियां भी बेहतर तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित होती हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, टीवी, रेफ्रिजरेटर और एलपीजी चूल्हा जैसे उपकरण लगभग हर घर में इस्तेमाल होते हैं और इनकी कुल बिजली व ऊर्जा खपत काफी अधिक होती है। ऐसे में इन पर स्टार रेटिंग लागू होने से राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की बड़ी बचत संभव है। साथ ही, सोलर इनवर्टर और वितरण ट्रांसफॉर्मर को इस दायरे में लाने से नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली वितरण व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी और दक्ष बनाया जा सकेगा। कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला उपभोक्ताओं, उद्योग और पर्यावरण तीनों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। एक ओर जहां लोगों के बिजली खर्च में कमी आने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर यह कदम भारत के ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में देखा जा रहा है।

मजबूत घरेलू मांग के सहारे रफ्तार पकड़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर जारी अस्थिरता और प्रतिकूल बाहरी परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च विकास पथ पर बने रहने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि देश की मजबूत घरेलू खपत और निवेश की निरंतर गति आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि को सहारा देती रहेगी। आरबीआई की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और देश की वित्तीय प्रणाली को लगातार सुदृढ़ करना ही केंद्रीय बैंक का मार्गदर्शक सिद्धांत है।

मल्होत्रा के अनुसार, भारत की आर्थिक बुनियाद इस समय कई मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि, नियंत्रण में बनी मुद्रास्फीति, वित्तीय और गैर-वित्तीय कंपनियों की सुधरती बैलेंस शीट, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और समय पर किए गए नीतिगत सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। यही कारण है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, भू-राजनीतिक तनावों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है।

आरबीआई गवर्नर ने इस बात पर भी जोर दिया कि घरेलू मांग भारतीय विकास कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। उपभोग में निरंतरता, बुनियादी ढांचे में बढ़ता निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। इसके साथ ही बैंकिंग प्रणाली की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है, जिससे कर्ज प्रवाह में सुधार आया है और उद्योगों व उपभोक्ताओं दोनों को समर्थन मिला है।

उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों और सतर्क मौद्रिक नीति के कारण वित्तीय प्रणाली झटकों को सहने में सक्षम बनी है। कम मुद्रास्फीति का माहौल न केवल आम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि निवेशकों के भरोसे को भी मजबूत करता है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार ने बाहरी दबावों के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम किया है, जिससे रुपये और वित्तीय बाजारों में स्थिरता बनी रही है।

संजय मल्होत्रा ने यह भी संकेत दिया कि आरबीआई आगे भी वित्तीय स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नीतिगत फैसले लेता रहेगा। उनका कहना था कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में जोखिमों पर सतत निगरानी और समय पर हस्तक्षेप बेहद जरूरी है, ताकि आर्थिक विकास की रफ्तार कायम रखी जा सके। कुल मिलाकर आरबीआई का आकलन यह दर्शाता है कि मजबूत घरेलू आधार और संतुलित नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले समय में भी उच्च वृद्धि के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी।

संपादकीय

सेहत का नया साल

आज हम एक नये साल में प्रवेश कर रहे हैं। नववर्ष पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। मंगलकामनाएं अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन नये वर्ष के आगमन के उत्साह में हम इकतीस दिसंबर को देर रात तक नये साल के जश्न में जुटे रहते हैं। इधर देश में प्रयोगधर्मी खानपान व नशीली पार्टियों का फैशन जैसा बन गया है। देर रात तक चलने वाली पार्टियों के बाद नये साल के पहले दिन ही हमारी नींद देर से खुलती है। फिर नये साल का पहला दिन ही सुस्ती और आलस्य के साथ शुरू होता है। कायदे से नये साल की शुरुआत एक ताजगीभरी सुबह के साथ होनी चाहिए। नये संकल्पों के लिए ऊर्जावान सुबह के साथ शुरू हो पहला दिन। निश्चित रूप से हमारा सामान्य जीवन व्यवहार बंधनों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन स्वस्थ जीवन के लिए कुछ नियम जरूरी भी हैं। दरअसल, नये दौर में हम, खासकर नई पीढ़ी एक अराजक जीवन जीने को अपनी शान समझती है। अमेरिका में हुए कुछ शोधों के बाद पता चला है कि सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना हमारी सेहत की गारंटी होती है। यह पुरानी भारतीय अवधारणा ही है। भारतीय समाज में ब्रह्ममुहूर्त में उठने की प्रतिष्ठित परंपरा रही है। इस समय प्रकृति एकाग्रता-ध्यान हेतु शांत होती है। शरीर के मल स्वतः बाहर निकलने की प्रक्रिया में होते हैं। यह तथ्यपरक है कि हम जितनी जल्दी नित्यकर्म से निवृत्त होते हैं, उतने जल्दी स्वस्थ होते हैं। नया साल न तो कोई जादू है और न ही चमत्कार करने वाला होता है। महज एक नये दिन मानक होता है। नया दिन बदलाव के संकल्प का और उससे जीवन को सुखमय बनाने का। यूं भी जब जनवरी के पहले दिन का आगमन होता है तो शीत का प्रकोप होता है, जिसके चलते जीवन की गति मंथर हो जाती है। संभवतः शीतजनित इस नीरसता व एकरसता को तोड़ने के लिए दुनिया में नववर्ष के उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने की परंपरा शुरू की गई होगी।

सही मायनों में उत्सव का उल्लास हमारे तन-मन को स्वस्थ और मंगलमय बनाने के लिए होता है। लेकिन इस दौरान हम खानपान को लेकर अराजक व्यवहार करने लगते हैं। दरअसल, हमारा शरीर बेहद संवेदनशील व हमारी सेहत के प्रति सचेत होता है। शरीर का अपना उन्नत सुरक्षा-तंत्र लगातार हमारे स्वास्थ्य की फिक्र करता है। वह शरीर को सर्दी-गर्मी के अनुरूप अपना ताप नियंत्रित कर हमारे जीवन की रक्षा करता है। वह बार-बार संकेतों से हमें सचेत करता है। हम उसकी आवाज अनसुनी कर देते हैं। एक सीमा तक वह इसे बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर असहाय होने की स्थिति में बीमार पड़ जाता है। अक्सर देखते हैं कि नये साल के जश्न, शादी-विवाह व मुफ्त की पार्टियों में हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन खाने-पीने की अराजकता पेट को लगातार परेशान करती है। उत्सव व पार्टी में हम सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा खा लेते हैं। योग दर्शन बताता है कि पेट को चार भागों में मानकर दो भाग खाने के लिये, एक पानी और एक आकाश तत्व के लिये रखें। आकाश तत्व यानी खाली रखने के लिए, जिससे पाचन की क्रिया सुगम होती है। हम किसी मशीन में भी कोई पदार्थ ठूंस-ठूंस कर भर दें, तो उसकी गति बाधित होती है। फिर पेट तो कोमलअंगी होता है। जापान के एक द्वीप में सौ से अधिक उम्र के सैकड़ों लोग मौजूद है, जिसने पश्चिमी शोधकर्ताओं को चकित किया। शोध में पता चला कि श्रमशील व प्रसन्न रहने वाले इस द्वीप के लोगों की एक खास आदत है, जब उन्हें लगता है कि खान पर्याप्त हो गया है, तो वे थाली का खाना उसी वक्त छोड़ देते हैं। यही उनकी लंबी उम्र का राज भी है। दरअसल, भूख हमारी शारीरिक जरूरत से अधिक मानसिक होती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे खाने की मात्रा में कमी होनी चाहिए। हम जीने के लिये खाएं, न कि खाने के लिए जीएं। अब चाहे नये साल की पार्टी हो या कोई पर्व-त्योहार, हमें संयमित भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। हल्का, सुपाच्य व कम भोजन जहां दवा है, वहीं गरिष्ठ व अधिक भोजन हानिकारक हो सकता है।

‘राष्ट्रहित सर्वोपरि’ के संकल्प के साथ करें अंग्रेजी नव वर्ष 2026 का स्वागत

> वैसे भी अब देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत नये संकल्प के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से करते हैं। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि पिछले वर्ष के दुख-दर्द भूलकर के खट्टी-मीठी यादों से सबक लेकर के अंग्रेजी नव वर्ष को पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाएं।

देश व दुनिया में अंग्रेजी नव वर्ष 2026 के स्वागत की जबरदस्त धूम मची हुई है, इस धूम-धाम को हम लोगों का जोशो-खरोश और चार-चांद लगाने का काम कर रहा है। हम सभी लोग नयी उम्मीद, नयी उमंग, नये विचार, नये संकल्प के साथ अपने-अपने अंदाज व तौर-तरीकों से अंग्रेजी नव वर्ष 2026 का हर्षोल्लास से स्वागत कर रहे हैं। हम लोग आशा कर रहे हैं कि नव वर्ष में शक्तिशाली राष्ट्र के सपने को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार धरातल पर तेज़ी से काम करेंगी, लेकिन हम लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए की यह कार्य हम देशवासियों के द्वारा राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प के बिना पूरा नहीं हो सकता है, हम जिस तरह से अपने हितों के प्रति जुनून के साथ समर्पित रहकर उनकी रक्षा करते हैं, उसी भाव से हमें नियम-कायदे-कानून में रहकर राष्ट्र के प्रति भी समर्पित भाव से रहना होगा, तब ही सशक्त विकसित भारत का निर्माण होगा। वैसे भी अब देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत नये संकल्प के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से करते हैं। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि पिछले वर्ष के दुख-दर्द भूलकर के खट्टी-मीठी यादों से सबक लेकर के अंग्रेजी नव वर्ष को पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाएं, हम सभी चाहते हैं कि इस नव वर्ष में हम अपने सभी सपनों को पूरा करें, अपनी व अपनों की झोलियों को खुशियों से भर देने का संकल्प लेकर उसके लिए तय रणनीति के अनुसार जीवन पथ पर कार्य करें। हम चाहते हैं कि बीते हुए समय पर विचार व आत्ममंथन करते हुए, नए लक्ष्य निर्धारित करते हुए, भविष्य में आने वाले जीवन को नयी दिशा देने

वाले हर सकारात्मक अवसर को हर हाल में अपनाएं। हम लोग अपनी आकांक्षाओं, संकल्पों के साथ ही नव वर्ष के इस विशेष अवसर को विभिन्न तरीकों से मनाने का कार्य करते हैं। लेकिन उपरोक्त भावों में अगर हम लोग हर वर्ष राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प को भी जोड़ लें तो देशवासियों के जीवन में चार-चांद लग सकते हैं, हम जल्द ही अपने सपनों के विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं।

वैसे तो नव वर्ष पर दुनिया भर के लोग एक नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही हम लोग बीते हुए कल की कड़वी यादों से सीख लेकर के एक नई शुरुआत भी करने का सकारात्मक प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बीते हुए कल को पीछे छोड़कर के एक नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए सभी आवश्यक आत्म-सुधार के संकल्पों के साथ नव वर्ष का स्वागत करें, हमें यही सिद्धांत राष्ट्रहित की रक्षा के लिए भी लागू करने चाहिए, वैसे भी देखा जाए अंग्रेजी हो या हिन्दू नव वर्ष यह अवसर हम सभी लोगों को सुख-शांति, धन-धान्य, स्वास्थ्य और जीवन पथ पर सफलता की आशाओं के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का कार्य अवश्य करता है। हम लोगों के द्वारा नव वर्ष मनाने का समय व रीति-रिवाज तो अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके मूल भाव पर गौर करें तो अधिकांश लोगों के लिए यह व्यक्तिगत जीवन में आनंद और व्यक्तिगत विकास के लिए की लिए रणनीति बनाकर के वर्ष भर उस रणनीति पर काम करने की शुरुआत का एक बेहतरीन अवसर होता है, बस हम लोगों को इस रणनीति में अब राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प को और जोड़ना है, जीवन पथ पर लक्ष्यों को तय करते हुए अब वह समय आ गया है कि जब हम राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प के साथ नव वर्ष की शुरुआत करें। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में आम लोगों की डिक्शनरी व आचरण से राष्ट्रहित सर्वोपरि दूर की बात होता जा रहा है, राष्ट्रहित पर व्यक्तिगत हित बहुत तेज़ी से हावी होते जा रहे हैं, लोग अपने क्षणिक लाभ के लिए राष्ट्र की बहुमूल्य संपदा, अमन-चैन, भाईचारे तक को दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए अब वह समय आ गया है कि जब हम राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प के साथ नव वर्ष की शुरुआत करें। आज अंग्रेजी नव वर्ष 2026 के अवसर पर मैं अपनी चंद पंक्तियों के माध्यम से आप सभी सम्मानित देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं -

“नववर्ष में प्रभु श्रीराम की कृपा से पूरी हों सभी आस,
नववर्ष बने खास तेजी से बढ़ें हमारा आत्म-विश्वास,
जीवन पथ पर सफल हों हमारा हर अच्छा प्रयास,
जीवन पथ की राहों में ना रहे मुश्किलों का वास,
हल पल परिपूर्ण रहें सकारात्मक ऊर्जा के साथ,
हमेशा बना रहें घर व दिल में प्रभु श्रीराम का वास।”

उपरोक्त चंद पंक्तियों से मैं अंग्रेजी नववर्ष 2026 की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इस नव वर्ष में हम सभी लोग राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानेंगे और आपसी वैमनस्य को भूलकर के फिर से एकजुट होकर के अपने जीवन की एक नई पारी की शानदार शुरुआत करते हुए देश निर्माण के लिए दिन-रात एकजुट होकर के कार्य करेंगे और देश का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे, वर्ष 2026 में हम देश में एक ऐसा बेहद शानदार सकारात्मक माहौल बनायेंगे, जिसमें हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो और जिसके दम पर भारत विकसित राष्ट्र बनकर जल्द विश्वगुरु बन सकें। इस उम्मीद के साथ ही मैं नव वर्ष की इस पावन बेला पर प्रभु श्रीराम से प्रार्थना करता हूं कि उम्मीदों के नव वर्ष 2026 में वह प्रत्येक देशवासी की झोली को खुशहाली से भर दें और देश में रामराज्य की अवधारणा को धरातल पर जल्द से जल्द साकार कर दें।

प्रेरणा

सम्राट अशोक और एक निर्णय जिसने इतिहास की दिशा मोड़

इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं, जो दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनके प्रभाव युगों तक महसूस किए जाते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के जीवन में भी एक ऐसा ही क्षण आया, जब एक साधारण माली के शब्दों ने एक सम्राट के मन, शासन और सोच की दिशा बदल दी। यह घटना केवल एक राजा की दुविधा की कथा नहीं है, बल्कि यह धैर्य, करुणा और विवेक के उस शाश्वत सत्य को उजागर करती है, जो हर युग में उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।

एक दिन सम्राट अशोक अपने राजदरबार में विराजमान थे। सीमावर्ती क्षेत्र से विद्रोह की गंभीर सूचना आई थी। संदेशवाहक ने बताया कि कुछ स्थानीय सरदारों और जनता ने कर व प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में बगावत कर दी है। यह खबर सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। अनुभवी मंत्री, सेनापति और सलाहकार अपने-अपने तर्क देने लगे। अधिकांश का मत था कि विद्रोह को तुरंत और कठोर दंड देकर कुचल दिया जाए, ताकि बाकी क्षेत्रों में भय बना रहे और शासन की शक्ति पर कोई प्रश्न न उठे। कुछ मंत्रियों ने यह भी कहा कि यदि अभी सख्ती नहीं दिखाई गई, तो अन्य प्रांत भी विद्रोह का साहस कर सकते हैं।

आदेश का मसौदा तैयार होने लगा। सैनिक टुकड़ियों को तैयार रहने का संकेत दिया जाने लगा। परंतु इस पूरे वातावरण के बीच अशोक का मन विचलित था। उन्होंने अनेक युद्ध देखे थे, सत्ता के लिए रक्तपात का मार्ग अपनाया था और विजय के साथ-साथ विनाश का दृश्य भी अपनी आंखों से देखा था। मंत्रियों की बातें तार्किक थीं, पर उनके भीतर कहीं एक असहजता थी, जिसे वे स्वयं भी स्पष्ट शब्दों में नहीं समझ पा रहे थे। अंततः उन्होंने दरबार स्थगित करने का आदेश दिया और कहा कि वे इस विषय पर बाद में निर्णय लेंगे।

दरबार से उठकर अशोक राजमहल के बगीचे में चले गए। वहां सन्नाटा था, हरियाली थी और पक्षियों की मधुर आवाजें थीं। यह वही स्थान था, जहां वे अक्सर चिंतन करने आते थे। चलते-चलते उनकी दृष्टि एक माली पर पड़ी, जो बड़े ध्यान से एक पौधे की टूटी हुई टहनी को सहारे के डंडे से बांध रहा था। टहनी आधी टूट चुकी थी, पत्ते मुरझाए हुए थे, लेकिन माली बड़े धैर्य से उसे ठीक करने में लगा था।

सम्राट कुछ देर उसे देखते रहे, फिर उन्होंने सहज जिज्ञासा से पूछा, “इस टहनी को काट क्यों नहीं देते? यह तो टूट चुकी है।” माली ने काम करते-करते सिर उठाया, महाराज को देखकर विनम्रता से झुका और बोला, “महाराज, यह अभी पूरी तरह मरी नहीं है। इसमें जीवन शेष है। अगर इसे थोड़ा सहारा और समय मिल जाए, तो यह फिर से हरी हो सकती है।” माली के शब्द सरल थे, लेकिन उनमें गहरा अर्थ छिपा था।

अशोक वहीं ठिठक गए। उनके मन में जैसे कोई दीपक जल उठा। विद्रोही क्षेत्र, कठोर दंड, तलवार, रक्तपात—सब एक क्षण में उनकी आंखों के सामने घूम गए। क्या विद्रोह भी उस टूटी टहनी की तरह नहीं है, जिसमें अभी जीवन शेष है? क्या हर समस्या का समाधान उसे काट देना, जला देना और कुचल देना ही होता है? या कभी-कभी धैर्य, संवाद और समझदारी से भी हालात बदले जा सकते हैं?

वे बिना कुछ कहे लौट आए। दरबार पुनः बुलाया गया, लेकिन इस बार स्वर बदला हुआ था। अशोक ने मंत्रियों से कहा कि दंड का आदेश रोक दिया जाए। इसके स्थान पर उन्होंने विद्रोही क्षेत्र में दूत भेजने, स्थानीय नेताओं से संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं को समझने का निर्णय लिया। कुछ मंत्रियों ने इस निर्णय पर आश्चर्य व्यक्त किया, कुछ ने चिंता जताई कि यह कमजोरी समझी जाएगी, लेकिन अशोक अपने निर्णय पर अडिग थे।

समय लगा। संवाद आसान नहीं था। अविश्वास था, शिकायतें थीं, वर्षों की उपेक्षा और असंतोष था। लेकिन धीरे-धीरे स्थिति बदलने लगी। प्रशासनिक सुधार किए गए, करों में राहत दी गई, स्थानीय लोगों को सम्मान दिया गया और उनकी बातों को सुना गया। कुछ समय बाद वही क्षेत्र, जो विद्रोह की आग में जल रहा था, शांत हो गया। बिना तलवार उठाए, बिना रक्त बहाए समस्या का समाधान हो गया।

उस दिन अशोक ने केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने शासन का एक नया मार्ग चुना था। उन्होंने समझा कि शक्ति का अर्थ केवल दंड देने की क्षमता नहीं है, बल्कि धैर्य रखने, सुनने और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी शक्ति ही है। हर समस्या तलवार नहीं मांगती, कुछ समस्याएं सहानुभूति और संवाद की मांग करती हैं।

यह घटना हमें यह सिखाती है कि जल्दबाजी में लिया गया कठोर निर्णय अक्सर स्थायी समाधान नहीं देता। चाहे शासन हो, समाज हो या व्यक्तिगत जीवन, हर टूटती हुई टहनी को तुरंत काट देना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार थोड़े धैर्य, थोड़े सहारे और थोड़े विश्वास से वही टहनी फिर हरी हो जाती है। आज के समय में, जब असहिष्णुता और त्वरित प्रतिक्रिया का दौर है, अशोक और माली की यह कथा और भी प्रासंगिक हो जाती है।

धैर्य कमजोरी नहीं है, बल्कि वह शक्ति है, जो विनाश को निर्माण में बदल सकती है। सम्राट अशोक का वह निर्णय हमें याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है, जो क्रोध पर विवेक को और हिंसा पर मानवता को प्राथमिकता दे। यही कारण है कि अशोक केवल एक विजेता राजा नहीं, बल्कि इतिहास में करुणा, शांति और धैर्य का प्रतीक बनकर अमर हो गए।

खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है अरावली का वजूद

वर्ष 2021 की हॉलीवुड व्यंग्य फिल्म ‘डोंट लुक अप’ में, दो अमेरिकी खगोलशास्त्री दुनिया को एक धूमकेतु के बारे में चेतावनी देते हैं, जो पृथ्वी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति एक अरबपति के झांसे में आ जाते हैं, जो यह दावा करता है कि उस आकाशीय पिंड में खरबों डॉलर के दुर्लभ तत्व हैं। आखिरकार, धूमकेतु पृथ्वी से टकराता है, जिससे एक वैश्विक आपदा बनती है।

काश! फिल्म के मुख्य किरदारों ने प्राकृतिक संसाधनों की लूट के भयानक परिणामों के बारे में संज्ञान लिया होता, जैसा कि उत्तर भारत के ‘हरे फेफड़े’ पुकारी जाने वाली और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अति संवेदनशील किंतु क्षतिग्रस्त की जा चुकी अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रस्तावित 100 मीटर की परिभाषा से साफ था तो फिल्म का शीर्षक ‘डोंट लुक अप, लुक डाउन’ होता। यह वही है, जिसकी चेतावनी महात्मा गांधी ने यह कहकर दी थी, ‘दुनिया में हर किसी की ज़रूरत के लिए काफी है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं।’

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर आधारित सभी विकास गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि मुख्य आवश्यक तत्वों के अत्यधिक खनन के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होते हैं और इसके लिए सख्त नियमों के अलावा प्रकृति द्वारा प्रदत्त पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्यांकन की भी ज़रूरत है। इसके सामाजिक प्रभाव भी होते हैं, जिनके लिए कोई माप-सूत्र मौजूद नहीं है। ऐसे में, अगर नीति निर्माताओं को गलती करनी भी पड़े, तो उन्हें लोगों और पर्यावरण के हित में गलती करनी चाहिए। इसी तरह, जब हिमालय के ग्लेशियर पिघलने लगे, तब एक ऐसा कथानक गढ़ने की कोशिश की गई जो उन दावों को चुनौती दे रहा था, जिसमें इस घटनाक्रम को जलवायु आपदा बताया गया था। भगवान का शुक्र है कि अब दुनिया पिघलते ग्लेशियरों के विनाशकारी परिणामों के प्रति जाग गई है। ग्लोबल वार्मिंग से आगे बढ़कर, दुनिया पहले ही ग्लोबल बॉइलिंग स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब है पहाड़ियों और जंगलों का अंधाधुंध दोहन, जो दुनिया को सिर्फ जलवायु आपदा की ओर धकेलेगा। चार राज्यों—गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 37 जिलों में 1.44 लाख वर्ग किमी में फैली अरावली पहाड़ियों में सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा और बेशक, संगमरमर जैसे मुख्य खनिजों का भरपूर भंडार है। इसके अलावा, ये पहाड़ियां लिथियम, निकेल, मोलिब्डेनम, नाइओबियम और टिन जैसे ज़रूरी खनिजों से भी भरपूर हैं। जैसे ‘डोंट लुक अप’ में अमेरिकी राष्ट्रपति को यह विश्वास दिलाया गया था कि धूमकेतु की आर्थिक संपत्ति बहुत ज़्यादा दौलत लाएगी, वैसे ही यह माना जा रहा है कि अरावली में मौजूद खनिज देश के आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी हैं। अगर ऐसा है, तो मुझे नहीं पता कि इतने बड़े पैमाने पर ‘सेव अरावली’ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। क्या लोग खनिज संपदा की आर्थिक कीमत नहीं समझते, जिसे किसी भी कीमत पर निकालना ज़रूरी है?

एक अरब साल से भी ज़्यादा पुरानी अरावली पहाड़ियों ने उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के रेगिस्तान बनने के विरुद्ध एक हरी दीवार का काम किया है। ये पहाड़ियां समृद्ध जैव विविधता का भंडार भी हैं; ये जमीन के नीचे के जलभंडारों की भरपाई करने में अहम भूमिका निभाती हैं और इन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रेगिस्तान की आगे बढ़ने की चाल को रोका है। लेकिन अरावली पट्टी में इंसानी दखल और विकास प्रक्रिया के कारण वन्यजीवों के आवासों और स्थानीय आजीविका को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। जैसे-जैसे रेगिस्तान फैल रहा है, देश की कड़ी मेहनत से हासिल की गई खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।

फरवरी, 2025 में संसद को बताया गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किए गए 2021 के भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण मानचित्र के अनुसार, रेगिस्तान तेज़ी से अन्न पैदा करने वाली कृषि भूमि की ओर बढ़ रहा है। पहले से ही, हरियाणा में 3.64 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा, पंजाब में 1.68 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 1.54 लाख हेक्टेयर भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुकी है। एक बार अरावली का स्वरूप नई परिभाषा के अनुसार बन गया तो भूमि क्षरण और भी तेज़ हो जाएगा। इससे तेज़ गर्म हवा, बार-बार धूल भरी आंधियां, बढ़ते तापमान का रास्ता खुल जाएगा; इसके साथ खेती के कारण गहरे जमीनी पानी के खत्म होने से, मिट्टी का कटाव और तेज होगा, जिससे कृषि भूमि की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। को लेकर प्रस्तावित नए मानकों पर बहस खनन और पर्यावरण पर केंद्रित है वहीं लंबी अवधि की खाद्य सुरक्षा के लिए उभरता खतरा नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन ने चेतावनी दी है कि मरुस्थलीकरण मिट्टी की उर्वरता को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिससे उपजाऊ ज़मीनें अर्धशुष्क हो जाती हैं। निश्चित रूप से, मरुस्थलीकरण इतना गंभीर मुद्दा है कि इसे सिर्फ दावों और वादों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। एक नई प्रबंधन योजना को लागू करने और ‘मज़बूत सुरक्षा’ के वादे अब पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं।

निःसंदेह, अरावली की पहाड़ियां महज रणनीतिक खनिजों के लिए एक प्राकृतिक भंडार नहीं हैं; वे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भी प्रदान करती हैं। प्रकृति प्रदत्त इन पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सेवाओं की वास्तविक आर्थिक लागत का पता नहीं लगाया गया है। एक बार जब यह मोल पता चल जाएगा, तो राष्ट्र को पहाड़ियों को बरकरार रखने की आर्थिक आवश्यकता का अहसास होगा, भले ही खनिजों को निकालने की आर्थिक लागत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। ‘द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ बायोडायवर्सिटी’ के मानदंडों के अनुसार अगर राष्ट्रीय लेखा-जोखा में धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण कैलास पर्वत और डल झील को आर्थिक मूल्य दिया जा सकता है, तो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली के लिए भी, इसी प्रकार का लागत-लाभ विश्लेषण किया जाना चाहिए।

अभियान

मोहरूपी अज्ञान से मुक्ति का मार्ग : गीता और रामचरितमानस का शाश्वत संदेश

गीता और रामचरितमानस भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के ऐसे दो दिव्य स्तंभ हैं, जिनका उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था को पुष्ट करना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके भीतर बसे मोहरूपी अज्ञान से मुक्त कर सच्चे आत्मबोध की ओर ले जाना है। दोनों ग्रंथ अलग-अलग कालखंडों में, अलग-अलग संदर्भों में प्रकट हुए, लेकिन उनका मूल संदेश एक ही है—अज्ञान ही सभी दुखों का मूल है और उससे मुक्ति का एकमात्र मार्ग ईश्वर की शरणागति, भक्ति और सही दृष्टि का विकास है।

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को युद्धभूमि में जो उपदेश देते हैं, वह केवल युद्ध नीति नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जीवन का दर्शन है। गीता का ग्यारहवां अध्याय श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप को समर्पित है, जहाँ अर्जुन को यह अनुभूति होती है कि जिस व्यक्ति को वह अपना सखा, सारथी और संबंधी समझ रहा था, वही सम्पूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। यह विराट दर्शन मनुष्य के सीमित अहंकार को तोड़कर उसे व्यापक सत्य से जोड़ता है। गीता में श्रीकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण ही जीव को मोह में डालता है—“तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्।” यह मोह ही प्रमाद, आलस्य और निद्रा के रूप में मनुष्य को जकड़ लेता

है और उसे सत्य से दूर रखता है। मनुष्य बाहरी सुखों को ही सब कुछ मान बैठता है और आत्मिक चेतना से कट जाता है।

यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सरल, सरस और भावपूर्ण भाषा में कहते हैं—“मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला।” अर्थात मोह ही सभी रोगों की जड़ है। मानस में श्रीराम का विराट, अलौकिक और दिव्य स्वरूप अनेक प्रसंगों में प्रकट होता है। कागभुशुण्डि जी के उपदेश हों या मंदोदरी का विलाप, हर जगह यह संदेश मिलता है कि श्रीराम केवल अयोध्या के राजा या दशरथ के पुत्र नहीं, बल्कि सम्पूर्ण सृष्टि के आधार, करुणा के सागर और भक्तवत्सल प्रभु हैं। मानस का सौंदर्य यही है कि वह गहन दार्शनिक सत्य को लोकभाषा में उतारकर जन-जन के हृदय तक पहुंचा देता है।

गीता और मानस दोनों इस बात पर बल देते हैं कि बाहरी कर्मकांड या दिखावटी धर्म से अधिक आवश्यक है मन की शुद्धि और दृष्टि का परिवर्तन। जब तक मनुष्य अपने भीतर के मोह, अहंकार और भय से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में गीता का सबसे बड़ा आश्वासन आता है—“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।” श्रीकृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के आडंबरों और संदेहों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह शरणागति कोई भय से भरी दासता नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास और प्रेम से भरा समर्पण है।

रामचरितमानस में यही भाव और अधिक करुणा के साथ प्रकट होता है। श्रीराम कहते हैं कि चाहे किसी पर कितने ही बड़े पाप क्यों न हों, यदि वह सच्चे मन से शरण में आ जाए तो मैं उसे कभी नहीं त्यागता। “कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू, आएं सरन तजउं नहिं ताहू।” यह पंक्ति मनुष्य को आश्वस्त करती है कि ईश्वर की करुणा किसी गणित या न्यायिक तराजू में नहीं बंधी है, बल्कि वह प्रेम और दया से प्रेरित है। जैसे ही जीव प्रभु के सम्मुख होता है, उसके असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।

गीता में श्रीकृष्ण अनन्य भक्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो लोग एकाग्र चित्त से केवल मेरा चिंतन और पूजन करते हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं का वहन मैं स्वयं करता हूं। यह कथन केवल भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की आंतरिक सुरक्षा, मानसिक संतुलन और आत्मिक उन्नति का भी आश्वासन है। मानस में यही भाव माता और बालक के रूपक से व्यक्त होता है—जिस प्रकार माता अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार प्रभु अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। यह तुलना ईश्वर को दूर, कठोर और दंड देने वाले रूप से हटाकर अत्यंत स्नेहिल और अपनत्व भरे रूप में प्रस्तुत करती है।

इन दोनों ग्रंथों का सार यह है कि संसार एक सागर की तरह है, जिसमें मोह, काम, क्रोध और लोभ की लहरें निरंतर उठती रहती हैं। यदि मनुष्य केवल अपनी बुद्धि, बल या चतुराई के सहारे इस सागर को पार करना चाहे, तो वह बार-बार डूबेगा। लेकिन यदि वह प्रभु की शरण में आकर अपने अहंकार को त्याग दे, तो वही सागर उसके लिए पार होने योग्य बन जाता है। गीता और मानस हमें यह भी सिखाते हैं कि शरणागति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि कर्तव्य करते हुए ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना है।

आज के समय में, जब मनुष्य बाहरी प्रगति के बावजूद भीतर से अधिक अशांत, भयभीत और अकेला महसूस कर रहा है, गीता और मानस का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविक विजय बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान और मोह पर विजय पाने में है। यदि हम इन अलौकिक ग्रंथों के सत्संग से अपने मन को संस्कारित करें, अपनी सोच को शुद्ध करें और ईश्वर की शरण में रहते हुए जीवन के संघर्षों का सामना करें, तो न केवल जीवन संग्राम में विजयी हो सकते हैं, बल्कि मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त कर सकते हैं। यही गीता और मानस का शाश्वत संदेश है—मोह से मुक्ति और प्रेमपूर्ण शरणागति के द्वारा परम सत्य की प्राप्ति।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

‘स्वागत’ : पिछले 22 वर्षों से गुजरात के नागरिकों का सरकार में विश्वास दृढ़ कर रहा प्लेटफॉर्म

22 वर्षों में ‘स्वागत’ प्लेटफॉर्म से 99 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निपटान किया गया

▸▸ निर्धारित समयसीमा में नागरिकों की समस्याओं के उचित निवारण के लिए ‘स्वागत 2.0’ ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स पद्धति लागू

▸▸ आवेदनों के समय पर निराकरण के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, अधिकारियों के परफॉर्मेंस के परीक्षण के लिए परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाया गया

गांधीनगर : नागरिकों तथा सरकार के बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी में विद्यमान क्षमता का अधिकतम् उपयोग कर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2003 को स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेज बाई एप्लिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी (‘SWAGAT’ – ‘स्वागत’) कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरल; परंतु सशक्त था कि नागरिक भय, विलंब और प्रक्रियागत अवरोधों के बिना सरकार के उच्चतम् स्तरों के समक्ष अपनी शिकायतें सीधे ही प्रस्तुत कर सकें। ‘स्वागत’ ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम का दायरा जिला, तहसील एवं ग्रामीण स्तर तक विस्तृत हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस पहल को आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल प्रभावशाली ढंग से संचालित कर रहे हैं। वर्ष 2003 से लेकर आज 22 वर्षों से ‘स्वागत’ प्लेटफॉर्म गुजरात के नागरिकों का राज्य सरकार में विश्वास दृढ़ कर रहा है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पिछले 22 वर्षों में इस प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हुए 99.10 प्रतिशत आवेदनों का सकारात्मक निपटान किया गया है।

‘स्वागत’ 2.0 ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स पद्धति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘स्वागत’ को एक सक्रिय एवं लोक केन्द्रित प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया था। अब मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में समय तथा टेक्नोलॉजी के साथ ‘स्वागत’ प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में 25 दिसंबर, 2024 को राज्य के सभी जिलों एवं सभी विभागों में ‘स्वागत 2.0’ ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स पद्धति लागू की गई है और साथ ही ‘स्वागत’ ऑनलाइन मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू की गई है। उल्लेखनीय है कि ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स पद्धति 25 दिसंबर, 2023 को ‘सुशासन दिवस’ के उपलक्ष्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्व एवं पंचायत विभाग तथा पाटण व खेडा जिलों में लागू की गई थी। पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद कुल 21,540 आवेदनों में से 90 प्रतिशत आवेदनों का समयसीमा में सकारात्मक समाधान किया गया। इस प्रकार; पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने के बाद आगामी सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर, 2024 को ‘स्वागत 2.0’ सभी जिलों में लॉन्च किया गया।

कैसे काम करती है ऑटो एस्केलेशन मैट्रिक्स पद्धति ?

आधुनिक ‘स्वागत’ सिस्टम की संरचना एक ऑटोमैटिक एस्केलेशन फ्रेमवर्क के आसपास की गई है, जो सुनिश्चित करता है कि शिकायतें किसी भी स्तर पर अवरुद्ध न हो जाएँ। ‘स्वागत 2.0’ में नागरिकों की समस्याओं का निश्चित समयसीमा में गुणात्मक निवारण लाने के लिए निपटान की समयसीमा निर्धारित की गई है। आवेदक की प्रस्तुति/शिकायत उस अधिकारी को ऑनलाइन माध्यम से भेजी जाती है, जिसकी उस प्रस्तुति/शिकायत के निवारण की सीधी जिम्मेदारी है। आवेदक की प्रस्तुति के प्रति सम्बद्ध अधिकारी को निर्धारित समयसीमा में आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। आवेदकों को भी पंजीकरण से लेकर अंतिम निवारण तक के प्रत्येक चरण पर उनकी शिकायत की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा अवगत कराया जाता है। यदि सम्बद्ध अधिकारी द्वारा निर्धारित समयसीमा में शिकायत का निवारण न किया जाए, तो वह शिकायत समयसीमा पूर्ण होने के बाद ऑटोमैटिक उसके एक लेवल ऊपर के अधिकारी के लॉगिन में ऑटो एस्केलेट होती है। इसके बाद उस उच्च अधिकारी को शिकायत का निवारण करना होता है। उच्चाधिकारी द्वारा शिकायत निवारण करना अनिवार्य है। प्रस्तुति का संतोषजनक तथा उचित ढंग से निवारण हुआ होने संबंधी वेरिफिकेशन होने के बाद ही प्रस्तुति का अंतिम निपटान हुआ माना जाता है। इसके अतिरिक्त; आवेदक अपनी शिकायत को लेकर हुई कार्यवाही से संतुष्ट न हों, तो वे फीडबैक देकर शिकायत को एक लेवल ऊपर के अधिकारी को एस्केलेट भी कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा भी इन आवेदनों की सघन निगरानी की जाती है।

शिकायतों के समय पर निवारण के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड

पोर्टल में प्राप्त आवेदनों का समय पर निवारण लाने के उम्दा उद्देश्य से विभिन्न मॉनिटरिंग डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा; अधिकारियों के परफॉर्मेंस के परीक्षण के लिए परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है, जिसके आधार पर यह जानकारी मिलती है कि किस जिले में किस प्रकार की शिकायतें अधिक संख्या में आती हैं और राज्य के विभिन्न जिलों से मिलने वाली शिकायतों के अनुसार किस तरह के नीतिगत परिवर्तनों की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि ‘स्वागत’ कार्यक्रम के माध्यम से कई नीतिगत निर्णय किए गए हैं; जिनमें मुख्यतः किसानोन्मुखी, भूमि अधिग्रहण, विद्यार्थी-उन्मुखी, गौचर भूमि अतिक्रमण, री-सर्वे, पुलिस से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

‘स्वागत’ कार्यक्रम के माध्यम से मोडदर गाँव के 118 किसानों की समस्या हुई समाप्त

पोरबंदर जिले की कुतियाणा तहसील के मोडदर गाँव में ‘स्वागत’ कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हुआ। मोडदर गाँव से पसवारी के बीच सुखभादर नदी पर पुल नहीं होने के कारण किसानों को पिछले 40 वर्षों से अपने खेत में 15 किलोमीटर घूमकर पहुँचना पड़ता था। इस संबंध में आवेदक श्री लखमणभाई नवघणभाई मोडेदरा ने तहसील एवं जिला स्तर पर शिकायत की और इसके बाद उनकी समस्या राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम तक पहुँची। आवेदक ने पुल न होने के कारण 118 किसानों को 3600 बीघा भूमि की खेती के रोजमर्रा के कार्य में पड़ने वाली कठिनाइयाँ प्रस्तुत की थीं। उनकी प्रस्तुति सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने पुल तथा सड़क के कार्य तत्काल पूर्ण करने के लिए सड़क एवं भवन सचिव तथा पोरबंदल जिला कलेक्टर को निर्देश दिए, जिसके परिणामस्वरूप मोडदर-पसवारी के बीच 9 करोड़ रुपए की लागत से माइनर ब्रिज, क्लवर्ट और तीन किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा।

पिछले 2 वर्ष में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने ली ‘स्वागत’ इकाई की मुलाकात

‘स्वागत’ ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम को समझने के लिए भारत सरकार के सचिव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि जैसे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालयों के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा ‘स्वागत’ इकाई की मुलाकात ली गई है। उन्होंने अपने राज्य में भी इस प्रकार की सुविधा लागू करने के बारे में जानकारी हासिल की।

वार्षिक राउंड अप - पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मण्डल 2025

उपलब्धियों, परिचालन उत्कृष्टता और विकास का एक ऐतिहासिक वर्ष,अहमदाबाद मंडल को भारतीय रेलवे स्तर पर नॉन फेयर रेवेन्यू (NFR) में 4th स्थान प्राप्त हुआ

कैलेंडर वर्ष 2025 पश्चिम रेलवे के गुजरात राज्य में एक ऐतिहासिक, परिवर्तनकारी एवं उपलब्धियों से परिपूर्ण वर्ष के रूप में उभरकर सामने आया है। इस वर्ष रेल अवसंरचना के विस्तार, सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों में संपर्क सुदृढ़ीकरण, औद्योगिक विकास को गति देने तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के माध्यम से पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल ने विकास की एक नई गाथा लिखी है।

माल लदान

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने वर्ष 2025–26 में अब तक माल ढुलाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं सशक्त प्रदर्शन किया है। 30 दिसंबर तक प्रदर्शन के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में 2024–25 की तुलना में समग्र रूप से सुधार दर्ज किया गया है।

▸▸ पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 26000 वैगन की अधिक लोडिंग की गई।

▸▸ पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 3889 रैक की अधिक लोडिंग की गई।

▸▸ समयपालन (Punctuality) में अहमदाबाद मण्डल भारतीय रेलवे पर 10 में 8वें स्थान पर रहा।जिसकी समयपालनता 93.93% रही।

▸▸ अहमदाबाद मण्डल ने पहली बार रिकॉर्ड कंटेनर लोडिंग पिछली साल से 13.11% अधिक हुई।

▸▸ खाद की लोडिंग पिछली साल की तुलना में इस वर्ष 19.11% अधिक रही।

▸▸ नमक की लोडिंग पिछली साल की तुलना में इस वर्ष 20.34% अधिक रही।

▸▸ इसी प्रकार, कुल वहन भार 3,53,003 मिलियन टन से बढ़कर 3,86,497 मिलियन टन हो गया, जिसमें लगभग 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई।

समग्र रूप से, ये आंकड़े वर्ष 2025–26 के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में परिचालन दक्षता एवं प्रदर्शन में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाते हैं।

राजस्व प्राप्ति

▸▸ अहमदाबाद मंडल को भारतीय रेलवे स्तर पर नॉन फेयर रेवेन्यू (NFR) में 4th स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि को देखते हुए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के लिए पश्चिम रेलवे को नॉन फेयर रेवेन्यू (NFR) शील्ड घोषित की गई है जो माननीय रेलमंत्री जी द्वारा प्रदान की जाएगी।

▸▸ अहमदाबाद मंडल को माल लदान में 7 वां प्राप्त हुआ है।

▸▸ पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान (अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025) राजस्व अर्जन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में मंडल के विभिन्न राजस्व स्रोतों में सतत वृद्धि परिलक्षित हुई है।

▸▸ यात्री राजस्व में अहमदाबाद मंडल ने 6.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 1247.31 करोड़ से 1326.87 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। इसी अवधि में यात्रियों की संख्या भी 9.14 प्रतिशत बढ़कर 274.80 लाख से 299.92 लाख हो गई।

▸▸ माल ढुलाई क्षेत्र में मंडल का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली रहा। माल राजस्व में 6.94 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4856.85 करोड़ से बढ़कर 5193.95 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। पार्सल राजस्व भी 1.09 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 56.15 करोड़ से 56.76 करोड़ तक पहुँचा।

▸▸ गैर-किराया राजस्व में उल्लेखनीय 86.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 5.82 करोड़ से बढ़कर 10.84 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त टिकट जाँच से होने वाली आय में 54.93 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 14.91 करोड़ से बढ़कर 23.10 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के 16 स्टेशनों असारवा, विरामगाम, ध्रांगध्रा, पालनपुर, महेसाणा, पाटन, कालोल, मणिनगर, सिद्धपुर, चांदलोड़िया, वटवा, हिम्मतनगर, उंझा, भिलडी एवं भचाऊ को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

▸▸ सामाखियाली स्टेशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22.05.2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत स्टेशन के रूप में किया गया।

▸▸ सभी 16 स्टेशनों पर कुल 515.03 करोड़ की लागत से सॉफ्ट अपग्रेडेशन कार्य प्रगति पर हैं।

▸▸ सॉफ्ट अपग्रेडेशन कार्यों में स्टेशन फसाड एवं परिभ्रमण क्षेत्रों का सुधार, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म शेल्टर एवं बैठने की सुविधाओं का विकास, 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (FOB) तथा कोच गाइडेंस सिस्टम की व्यवस्था शामिल है।

▸▸ इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन-अनुकूल उन्नत शौचालय, उन्नत पार्किंग, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, संकेतक (साइनेज), हरित सौंदर्यीकरण, रिटायरिंग रूम, डॉर्मिटरी तथा उन्नत टिकटिंग एवं सुरक्षा प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं।

▸▸ प्रमुख पुनर्विकास (Major Upgradation) कार्य के अंतर्गत अहमदाबाद स्टेशन पर 2,379.00 करोड़, साबरमती बीजी एवं साबरमती जंक्शन पर संयुक्त रूप से 334.92 करोड़ तथा न्यू भुज स्टेशन पर 202.86 करोड़ की लागत से कार्य प्रगति पर हैं।

नई रेल लाइन/ गेज परिवर्तन

▸▸ आंबलियासन–विजापुर-मोटी आदराज रेलवे लाइन 82 किमी का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब यह रेलवे लाइन मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित होकर यात्रियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित परिचालन के लिए तैयार है।

▸▸ हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा रेलखंड (लगभग 55 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब यह सेक्शन यात्रियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित परिचालन के लिए तैयार है।

▸▸ कलोल-कडी-कटोसन रोड रेल लाइन का गेज परिवर्तन सहित विद्युतीकरण (38 किमी), जो गांधीनगर एवं महेसाणा जिलों को कवर करता है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा।

▸▸ महेसाणा–पालनपुर रेल खंड का दोहरीकरण (65.10 किमी), जो बनासकांठा, पाटन एवं महेसाणा जिलों को कवर करता है, दिल्ली–अहमदाबाद राजधानी मार्ग पर शेष अंतिम सिंगल लाइन अंतर को समाप्त करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा।

▸▸ बेचराजी–रणुज रेल खंड का गेज परिवर्तन (40 किमी), जो महेसाणा, पाटन एवं अहमदाबाद के जिलों को कवर करता है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति तथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप किया गया।

▸▸ साबरमती–बोटाद रेल खंड का विद्युतीकरण (106 किमी) पूरा होने के साथ ही गुजरात में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण सुनिश्चित हुआ।

▸▸ सामाख्याली-गांधीधाम-आदिपुर लाइन का चौहरिकरण (63.67 किमी) का कार्य प्रगति पर है।

▸▸ अहमदाबाद बाईपास के हिस्से के रूप में बारेजड़ी नांदेज (गेरतपुर) और साणंद के बीच 38.20 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। बारेजड़ी नांदेज और साणंद के बीच इस चौथी लाइन का निर्माण इन क्षमता संबंधी बाधाओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगा।

रोड अंडर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण

2025–26 के दौरान पश्चिम रेलवे के अंतर्गत गुजरात राज्य में 15 रेलवे क्रॉसिंग को हटाकर उनके स्थान पर 12 रोड अंडर ब्रिज और 3 रोड ओवर ब्रिज का निर्माण पूर्ण किया गया। पूर्ण किए गए रोड ओवर ब्रिज (ROB) रोड अंडर ब्रिज (RUB) एवं सबवे कार्यों में विरामगाम–सामाखियाली, अहमदाबाद–पालनपुर, पालनपुर–सामाखियाली, मेहसाणा–पाटन-भिलड़ी तथा खोडियार–गांधीनगर जैसे रेलखंडों में अनेक समपार फाटकों का उन्मूलन आरयूबी/आरओबी के निर्माण द्वारा किया गया, जिनमें अधिकांश में कवरड अप्रोच भी प्रदान की गई। अधिकांश कार्य जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच पूर्ण रूप से पूरे किए गए, ये परियोजनाएँ मेहसाणा, गांधीनगर, कच्छ, सुरेन्द्रनगर एवं बनासकांठा जैसे जिलों में फैली हुई हैं, जिससे सड़क-रेल संपर्क और सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

नई ट्रेन सेवा

▸▸ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 मई, 2025 को वेरावल-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दाहोद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

▸▸ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त, 2025 को गुजरात का दौरा किया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी दो महत्वपूर्ण नई रेल सेवाओं कटोसन रोड और साबरमती के बीच पहली मेमू ट्रेन सेवा तथा बेचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी को अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।

संरक्षा

▸▸ अहमदाबाद मंडल में यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 82.57 किमी ट्रैक का नवीनीकरण किया गया।

▸▸ यार्ड में अवरोधों को हटाया गया ताकि ट्रेनों का संचालन बाधारहित हो सके।

▸▸ 205 किमी लंबाई में बाउंड्री वॉल और फेंसिंग का निर्माण किया गया ताकि ट्रैक की सुरक्षा और बढ़ाई जा सके।

▸▸ पलनपुर–समाख्याली खंड में 6 स्थायी गति प्रतिबंधों को हटाया गया, जिससे ट्रेन संचालन और अधिक सुचारू हुआ।

▸▸ 20 पुलों की मजबूतीकरण कार्य पूरे किए गए ताकि संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

▸▸ 15 रेल फाटक हटाए गए और उनकी जगह रोड ओवर ब्रिज (ROB) और रोड अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किया गया, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कम हुआ और यात्रियों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की वनवासी विद्यार्थियों के प्रति अनूठी संवेदना

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वनवासी विद्यार्थियों के प्रति संवेदना दिखाते हुए विशेष समय निकालकर बुधवार को गांधीनगर में डांग के बच्चों के साथ मुलाकात की।

डांग जिले के मालेगाम के विद्यालय के शिक्षक सहित 150 से अधिक विद्यार्थी शैक्षणिक यात्रा के दौरान जब गांधीनगर आए, तब मुख्यमंत्री के साथ उनकी यह सहज मुलाकात आदिजाति विद्यार्थियों के अविस्मरणीय स्मृति बन गई।

मुख्यमंत्री ने इन बच्चों से उन्हें पढ़ाई के लिए मिल रही अत्याधुनिक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की।

सांसद श्री गोविंदभाई धोळकिया की ट्रस्टीशिप अंतर्गत संचालित प्रयोशा प्रतिष्ठान द्वारा डांग जिले के मालेगाम में वनवासी विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण शिक्षा तथा विकास का अनूठा सेवायज्ञ चल रहा है।

प्रयोशा प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 2002 से शुरू हुए संतोकबा धोळकिया विद्या मंदिर (निवासी शाला) में डांग जिले के 142 सुदूरवर्ती गाँवों के 400 से अधिक बच्चे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

▸▸ मुख्यमंत्री ने विशेष समय देकर डांग के वनवासी बच्चों के साथ संवाद-मुलाकात की

▸▸ डांग जिले के मालेगाम के विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात बनी अविस्मरणीय स्मृति

इस विद्यालय में पढ़कर इस वर्ष 1 विद्यार्थी आईआईटी-दिल्ली तथा 2 विद्यार्थी आईआईटी-रुड़की व गोवा में हैं। पूर्व में इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले 182 विद्यार्थी इंजीनियर, 22 विद्यार्थी डॉक्टर, 36 विद्यार्थी शिक्षक बने हैं और लगभग 65 विद्यार्थियों ने पैरामेडिकल की शिक्षा प्राप्त की है। मुख्यमंत्री इस विवरण से भी प्रभावित हुए।

इस अवसर पर केबिनेट मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, संस्था के अग्रणी श्री पी. पी. स्वामी तथा विद्यालय के शिक्षक उपस्थित रहे।

गुजरात के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों के विरुद्ध सज्ज करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोर कमिटी तथा टास्कफोर्स का गठन

▸▸ आधुनिक एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग से संभावित साइबर खतरे के विरुद्ध राज्य सरकार की पूर्व तैयारी

▸▸ राज्य के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर में साइबर सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा के साथ रणनीतिक रोडमैप तैयार किया जाएगा

गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा राज्य के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों के विरुद्ध सज्ज करने के लिए कोर कमिटी तथा टास्कफोर्स का गठन किया गया है। यह कोर कमिटी तथा टास्कफोर्स राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा संबंधी जरूरी कार्य, प्रशिक्षण, विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी तथा साइबर जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा कर रोडमैप प्रस्तुत करेगी। राज्य की 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में अब स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड तथा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) जैसे आधुनिक सिस्टम्स शामिल किए गए होने के कारण ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर में साइबर हमलों की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन विभाग (ईपीडी) द्वारा 11 सदस्यीय कोर कमिटी तथा 19 सदस्यीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है। यह कोर कमिटी तथा टास्कफोर्स ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आईटी एवं साइबर सुरक्षा नीति तथा उसकी घटनाओं के प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त; उसमें आवश्यक सुधार तथा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का निर्माण करने के लिए रोडमैप भी प्रस्तुत करेगी। इसके लिए शैक्षणिक संस्थाओं तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ भागीदारी भी की जाएगी और साइबर ड्रिल तथा प्रशिक्षण के साथ जागरूकता कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय व राज्य की एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाएगा। राज्य के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों के विरुद्ध चाकचौबंद बनाने के लिए एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वग्राही विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वग्राही तथा सर्वसमावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण जन हितकारी निर्णय किए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से राज्य की सभी 34 जिला पंचायतों के अध्यक्षों को 1 करोड़ रुपए का विवेकाधीन अनुदान सम्बद्ध जिलों के स्थानीय महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए आवंटित करने के दिशानिर्देश दिए हैं।

राज्य में विधायकों को विकेन्द्रित जिला योजना कार्यक्रम अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान आवंटित करने की परंपरा है।

▸▸ 34 जिलों की जिला पंचायतों के अध्यक्षों को 1 करोड़ रुपए का वार्षिक विवेकाधीन अनुदान स्थानीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवंटित किया जाएगा

मुख्यमंत्री के समक्ष जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपने जिले में ग्रामीण विकास कार्यों को वेग मिले और स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जा सके; इस आशय से जिला पंचायत अध्यक्षों को भी विवेकाधीन अनुदान आवंटित करने की प्रस्तुतियाँ-मांग की थीं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन प्रस्तुतियों पर सकारात्मक तथा त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए यह एक करोड़ रुपए का विवेकाधीन अनुदान जिला पंचायत अध्यक्ष को आवंटित करने के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को दिया है।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल और पंजाब नेशनल बैंक के बीच समझौता ज्ञापन

पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहतर बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MoU विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सैलरी और पेंशन खाते के माध्यम से सुविधाजनक वित्तीय सेवाओं और आकर्षक लाभ प्रदान करता है।

MoU पर हस्ताक्षर निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए:

पश्चिम रेलवेः श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक एवं श्री सिद्धार्थ, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, अहमदाबाद मंडल

पंजाब नेशनल बैंकः श्री विनिश चावला, क्षेत्रीय प्रबंधक गुजरात, श्री जगदीश गुप्ता, AGM मार्केटिंग और श्री कुणाल चटर्जी, मुख्य प्रबंधक

सैलरी और पेंशन खातों की प्रमुख विशेषताएँ:

सैलरी खाता:

▸▸ टर्म इंश्योरेंसः 10 लाख (NEO वेरिएंट को छोड़कर)

▸▸ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (PAI): 100–125 लाख

▸▸ एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (AAI): 200–250 लाख

▸▸ लॉकर किराए पर 100% तक छूट

▸▸ विशेष डेबिट कार्ड ऑफ़र

▸▸ परिवार के सदस्यों के लिए शून्य शेष खाते

पेंशन खाता:

▸▸ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (PAI): 15–30 लाख

▸▸ एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (AAI): 30–60 लाख

▸▸ हॉस्पी-कैशः 30,000–90,000

▸▸ रिटेल लोन पर ब्याज दर में छूट

▸▸ वार्षिक स्वास्थ्य जांच और असीमित टेली-कंसल्टेशन

▸▸ डिजिटल पर्सनल/पेंशन लोन सुविधा

यह सहयोग पश्चिम रेलवे की कर्मचारियों और पेंशनरों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे उन्हें आधुनिक, सुविधाजनक और वित्तीय रूप से लाभकारी सेवाएँ उपलब्ध हों।

इंटीग्रेटेड सिरामिक पार्क जांबुडिया-पानेली : एक विशिष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ औद्योगिक विकास का नया केन्द्र

मोरबी से वैश्विक बाजारों तक : वीजीआरसी राजकोट में एडवांस्ड सिरामिक्स में रणनीतिक निवेश के अवसर

गांधीनगर, 31 दिसंबर : जांबुडिया-पानेली में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा विकसित किए गए इंटीग्रेटेड सिरामिक पार्क के लोकार्पण को राज्य के औद्योगिक इतिहास में एक मील के पत्थर समान उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यह महत्वपूर्ण पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के विजन को साकार करने वाली दिशा में एक सशक्त कदम है। जीआईडीसी इंटीग्रेटेड सिरामिक पार्क गुजरात के उत्पाद क्षेत्र के भविष्य को मजबूत आधार देता है और एक परिवर्तनशील अवसर प्रदान करता है।

जांबुडिया-पानेली में जीआईडीसी का रणनीतिक औद्योगिक विकास

जीआईडीसी द्वारा मोरबी-राजकोट औद्योगिक पट्टे में जांबुडिया-पानेली में एक महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड सिरामिक पार्क विकसित किया जा रहा है। 1050 एकड़ क्षेत्र में फैला यह पार्क विश्वविख्यात मोरबी सिरामिक क्लस्टर के निकट होने के कारण मजबूत एवं स्थापित औद्योगिक इकोसिस्टम का पूरा लाभ उठाता है।

मूल्य श्रृंखला में विस्तार तथा औद्योगिक प्रभाव

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की संरचना सिरामिक उद्योग की समग्र मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति को विस्तृत करने के लिए की गई है। पार्क में मुख्यतः टाइल्स तथा सेनेटरी वेयर उत्पादन पर बल दिया जाएगा तथा औद्योगिक एवं एडवांस्ड सिरामिक्स जैसे उच्च मूल्य वाले और विशिष्ट सेगमेंट्स में नए निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह पहल गुजरात को वैश्विक सिरामिक उत्पाद मानचित्र पर और मजबूत स्थान दिलाएगी।

लॉजिस्टिक्स तथा रणनीतिक कनेक्टिविटी

जांबुडिया-पानेली सिरामिक पार्क को उत्तम लॉजिस्टिक्स तथा कनेक्टिविटी का लाभ मिलता है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) संख्या 27 से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि मोरबी का निकटस्थ रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा; राजकोट में स्थित हीरासर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 70 किलोमीटर तथा मकनसर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो केवल 5 किलोमीटर दूर है। नवलखी (48 किलोमीटर), कंडला (139 किलोमीटर) और मुंद्रा (195 किलोमीटर) जैसे मुख्य बंदरगाहों की निकटता वैश्विक निर्यात के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है।

बेस्पोक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा आधुनिक सुविधाएँ

इस पार्क की विशेषता यह है कि यहाँ उद्योगों की निश्चित आवश्यकताओं के अनुरूप बेस्पोक इन्फ्रास्ट्रक्चर (विशिष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा विशिष्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। एस्टेट में कॉमन डिसप्ले सेंटर, एनएबीएल-प्रमाणित प्रयोगशाला से युक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा नवाचारा को प्रोत्साह देने एवं कार्यबल की कुशलता बढ़ाने के लिए कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

उद्योगों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर 30 एमएलडी क्षमता वाली समर्पित जलापूर्ति व्यवस्था विकसित की जाएगी। विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए एस्टेट में तीन सबस्टेशन हेतु भूमि आवंटित कर दी गई है; जिनमें दो 66 केवी और एक 220 केवी क्षमता वाले सबस्टेशन होंगे। इसके अतिरिक्त; पर्यावरणीय रूप से दायित्वपूर्ण कामकाज सुनिश्चित करने हेतु ठोस कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए भी सुविधा उपलब्ध रहेगी।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) – कच्छ एवं सौराष्ट्र : औद्योगिक विकास का सशक्त मंच

आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) – कच्छ एवं सौराष्ट्र के दौरान राजकोट में क्षेत्र के सिरामिक्स, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स तथा ग्रीन एनर्जी आदि से जुड़े अग्रणी उद्योगों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 11 तथा 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में आयोजित होने वाली यह कॉन्फ्रेंस स्थानीय उद्योगों, उद्योग अग्रणियों तथा निवेश भागीदारों के लिए सहयोग एवं वृद्धि के नए अवसरों का सृजन करेगी। प्रतिनिधि जांबुडिया-पानेली सिरामिक पार्क को औद्योगिक विकास, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तथा कौशल विकास के मॉडल के रूप में देख रहे हैं। मोरबी के आसपास उपलब्ध विशाल एवं कुशल मानव संसाधन तथा गुणवत्तायुक्त ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस मजबूत आधार के कारण यह पार्क सिरामिक क्षेत्र में गुणवत्ता तथा टेक्नोलॉजिकल प्रगति का अग्रणी केन्द्र बना है।

सीजीएसटी दफ्तर में रिश्वत का बड़ा खेल उजागर, आईआरएस अधिकारी समेत पांच गिरफ्तार

लखनऊ। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने झांसी स्थित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कार्यालय में फैले रिश्वतखोरी के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एक आईआरएस अधिकारी सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तलाशी के दौरान 1.60 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, जेवरात और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीबीआई के अनुसार यह पूरा मामला जीएसटी चोरी से जुड़े मामलों में निजी कंपनियों को राहत दिलाने और जांच को प्रभावित करने के एवज में मोटी रिश्वत मांगने से जुड़ा है, जिसने कर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीबीआई द्वारा जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि झांसी सीजीएसटी में तैनात डिप्टी कमिश्नर आईआरएस प्रभा भंडारी पर आरोप है कि उन्होंने जीएसटी चोरी के मामलों में कार्रवाई से बचाने और अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले एक निजी फर्म से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस मांग को लेकर शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने पूरे मामले की गोपनीय जांच शुरू की और पुख्ता सबूत जुटाने के बाद जाल बिछाया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस पूरे लेनदेन में विभाग के अन्य अधिकारी, एक अधिवक्ता और एक निजी कंपनी का मालिक भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।

बुधवार को सीबीआई की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 70 लाख रुपये लेते समय सीजीएसटी के अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपितों के पास से 70 लाख रुपये नकद बरामद किए गए, जिससे मामले की पुष्टि हो गई। इसके बाद सीबीआई ने तत्काल आगे की कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, निजी कंपनी के मालिक राजू मंगतानी और बिचौलिये की भूमिका निभाने वाले अधिवक्ता नरेश कुमार गुप्ता को भी हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसी का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था और रिश्वत की रकम कई किस्तों में वसूली जानी थी।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने सभी आरोपितों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जहां से 90 लाख रुपये अतिरिक्त नकद, कीमती जेवरात और संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। इन बरामदगियों के साथ ही कुल जब्त नकदी की राशि 1.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की जांच से और भी वित्तीय अनियमितताओं और अन्य संभावित संलिप्त लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या इस नेटवर्क के तार किसी अन्य शहर या राज्य के सीजीएसटी कार्यालयों से भी जुड़े हुए हैं।

सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि सभी गिरफ्तार आरोपितों को मेडिकल परीक्षण के बाद संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही यह भी संकेत दिए गए हैं कि जांच का दायरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और कर चोरी तथा रिश्वतखोरी से जुड़े इस पूरे तंत्र की गहराई से जांच की जा रही है। इस कार्रवाई को सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह साफ हो गया है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ भी कानून अपना काम करेगा।

2026 में भी विकास की रफ्तार नहीं थमेगी, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था रहेगी मजबूत

नई दिल्ली। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका भारत आने वाले साल 2026 में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार दिख रहा है। मजबूत आर्थिक वृद्धि, नियंत्रित महंगाई, स्थिर और सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली तथा लगातार बढ़ता निवेश विश्वास ऐसे कारक हैं, जो भारत की विकास यात्रा को निरंतर गति दे रहे हैं। वर्ष 2025 में हासिल हुई तेज आर्थिक रफ्तार को बनाए रखने के लिए सरकार ने सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और बुनियादी ढांचे से लेकर उद्योग, सेवा और वित्तीय क्षेत्रों तक निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नीतिगत प्रयासों के चलते वैश्विक आर्थिक सुस्ती और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में भी दुनिया के लिए एक स्थिर और आकर्षक ग्रोथ इंजन बनी रहेगी।

भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जीवन और कारोबार को आसान बनाने के लिए लगातार नीतिगत कदम उठा रही है। केंद्र सरकार का फोकस पूंजीगत व्यय बढ़ाने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन को तेज करने पर है। वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में बड़े प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इन उपायों से घरेलू मांग मजबूत होगी और विदेशी निवेशकों के लिए भारत और अधिक भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में उभरेगा।

आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने 4.18 ट्रिलियन डॉलर की सकल घरेलू उत्पाद के साथ जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि भारत की दीर्घकालिक विकास क्षमता और मजबूत घरेलू बाजार को दर्शाती है। अर्थशास्त्रियों और वैश्विक एजेंसियों का अनुमान है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो साल 2030 तक भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर में लगातार मजबूती देखी गई है और वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में यह 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को अग्रणी स्थान दिलाती है।

महंगाई के मोर्चे पर भी हालात राहत देने वाले रहे हैं। खुदरा मुद्रास्फीति साल 2025 की शुरुआत में 4.26 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो नवंबर तक घटकर 0.71 प्रतिशत पर आ गई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई नरमी और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार इस गिरावट के प्रमुख कारण रहे। नियंत्रित महंगाई ने उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को सहारा दिया है और खपत आधारित वृद्धि को मजबूती प्रदान की है। इसके साथ ही सरकार राष्ट्रीय खातों के आधार वर्ष को 2022-23 में बदलने की प्रक्रिया पर काम कर रही है, जिससे जीडीपी गणना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और अधिक सटीक बनाया जा सके।

सुधारों के मोर्चे पर भी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। वर्ष 2025 के अंत में जीएसटी दरों में संभावित कटौती और नए श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन से उद्योग जगत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे कर संरचना सरल होगी, अनुपालन आसान बनेगा और संगठित क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर भी बाजार और उद्योग जगत में काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अर्थव्यवस्था को और गति देने, निवेश को बढ़ावा देने और सुधारों को मजबूती प्रदान करने वाले अतिरिक्त उपायों की घोषणा की अपेक्षा की जा रही है।

01 जनवरी 2026 से भावनगर रेलवे मंडल पर नया टाइम टेबल लागू, भावनगर मंडल के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर 01 जनवरी, 2026 से नई समय सारणी लागू की जा रही है। इसमें कुछ ट्रेनों की गति बढ़ाई जा रही है, जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इस बार भावनगर मंडल से होकर चलने वाली 04 ट्रेनों को वर्तमान निर्धारित समय से पहले तथा 08 ट्रेनों को वर्तमान निर्धारित समय से विलंब/देरी से चलाया जाएगा। भावनगर मंडल से होकर जाने वाली 17 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है, साथ ही यात्रा में लगने वाले समय में 05 मिनट से लेकर 50 मिनट तक की कमी की गई है। ट्रेनों की गति बढ़ाए जाने के फलस्वरूप यात्री ट्रेनों के परिचालन समय मे कमी आई है। इसका पूरा लाभ यात्रियों को मिलेगा व उन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने में समय की बचत होगी।

प्रारंभिक स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनें

1.ट्रेन नंबर 59228 भावनगर-सुरेन्द्रनगर पैसेन्जर, भावनगर टर्मिनस स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 05.10 बजे की बजाय 05.05 बजे प्रस्थान करेगी।
2.ट्रेन नंबर 59234 भावनगर-सुरेन्द्रनगर पैसेन्जर, भावनगर टर्मिनस स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 13.40 बजे की बजाय 13.30 बजे प्रस्थान करेगी।
3.ट्रेन नंबर 19209 भावनगर-ओखा दैनिक एक्सप्रेस, भावनगर टर्मिनस स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 22.10 बजे की बजाय 22.00 बजे प्रस्थान करेगी।
4.ट्रेन नंबर 59554 बोटाद-गांधीग्राम पैसेन्जर, बोटाद स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 17.10 बजे की बजाय 17.00 बजे प्रस्थान करेगी।

प्रारंभिक स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय से देरी से प्रस्थान करने वाली ट्रेनें

1.ट्रेन नंबर 16333 वेरावल-तिरूवनंतपुरम सेन्ट्रल एक्सप्रेस वेरावल स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 06.50 बजे की बजाय 06.55 बजे प्रस्थान करेगी।
2.ट्रेन नंबर 11463 वेरावल-जबलपुर एक्सप्रेस वेरावल स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 10.05 बजे की बजाय 10.10 बजे प्रस्थान करेगी।
3.ट्रेन नंबर 11465 वेरावल-जबलपुर एक्सप्रेस वेरावल स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 10.05 बजे की बजाय 10.10 बजे प्रस्थान करेगी।
4.ट्रेन नंबर 26902 वेरावल-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस वेरावल स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 14.40 बजे की बजाय 14.45 बजे प्रस्थान करेगी।
5.ट्रेन नंबर 19204 वेरावल-बान्द्रा एक्सप्रेस वेरावल स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 18.40 बजे की बजाय 19.00 बजे अर्थात् 20 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी।
6.ट्रेन नंबर 59215 भाणवड-पोरबंदर पैसेन्जर भाणवड स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 21.50 बजे की बजाय 22.40 बजे अर्थात् 50 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी।
7.ट्रेन नंबर 59555 गांधीग्राम-बोटाद पैसेन्जर गांधीग्राम स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 18.50 बजे की बजाय 19.00 बजे प्रस्थान करेगी।
8.ट्रेन नंबर 59271 बोटाद-भावनगर पैसेन्जर बोटाद स्टेशन से वर्तमान निर्धारित समय 15.45 बजे की बजाय 15.50 बजे प्रस्थान करेगी।

उल्लेखनीय है कि भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर पीट लाइन की मरम्मत हेतु चल रहे कार्य की वजह से जो ट्रेनें 25 जनवरी, 2026 तक निरस्त की गई हैं, वे निरस्त हीं रहेंगी तथा उन ट्रेनों पर यह परिवर्तित समय कार्य पूर्ण होने के पश्चात लागू होगा।

सोना वायदा में 1416 रुपये और चांदी वायदा में 14298 रुपये की गिरावट: क्रूड ऑयल वायदा में 26 रुपये की वृद्धि

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 746336.83 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 56524.94 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 689793.44 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 34891 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3533.58 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 45535.32 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 136327 रुपये के भाव पर खूलकर, 136327 रुपये के दिन के उच्च और 135116 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 136666 रुपये के पिछले बंद के सामने 1416 रुपये या 1.04 फीसदी लुढ़ककर 135250 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 810 रुपये या 0.73 फीसदी गिरकर 110105 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 56 रुपये या 0.41 फीसदी की तेजी के संग 13760 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 133586 रुपये के भाव पर खूलकर, 133700 रुपये के दिन के उच्च और 131950 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1544 रुपये या 1.15 फीसदी गिरकर 132430 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 136381 रुपये के भाव पर खूलकर, 136381 रुपये के दिन के उच्च और 133557 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 135031 रुपये के पिछले बंद के सामने 441 रुपये या 0.33 फीसदी गिरकर 134590 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 241400 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 242000 रुपये और नीचे में 232228 रुपये पर पहुंचकर, 251012 रुपये के पिछले बंद के सामने 14298 रुपये या 5.7 फीसदी गिरकर 236714 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 13714 रुपये या 5.43 फीसदी गिरकर 238740 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 13648 रुपये या 5.41 फीसदी घटकर 238802 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कमोडिटी वायदाओं में 56524.94 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 689793.44 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 45535.32 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 34891 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 7842.42 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 1.95 रुपये या 0.15 फीसदी गिरकर 1280 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 9.5 रुपये या 3.16 फीसदी की तेजी के संग 310 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.9 रुपये या 0.64 फीसदी लुढ़ककर 296.6 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 2.6 रुपये या 1.35 फीसदी की तेजी के संग 195 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3054.73 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5229 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5262 रुपये और नीचे में 5204 रुपये पर पहुंचकर, 26 रुपये या 0.5 फीसदी बढ़कर 5261 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 22 रुपये या 0.42 फीसदी की मजबूती के साथ 5261 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 360 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 360 रुपये और नीचे में 342 रुपये पर पहुंचकर, 357.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 14.3 रुपये या 4 फीसदी गिरकर 343.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 14.4 रुपये या 4.02 फीसदी की गिरावट के साथ 343.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 1025 रुपये पर खूलकर, 21 रुपये या 2.06 फीसदी औंधकर 1000 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 17644.35 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 27890.97 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 7141.71 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 315.66 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 24.53 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 360.51 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 388.88 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2649.46 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19145 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 91703 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 25699 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 416435 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 47103 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17348 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40581 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 105233 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 19770 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 38094 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 35000 पॉइंट पर खूलकर, 35252 के उच्च और 34736 के नीचले स्तर को छूकर, 918 पॉइंट घटकर 34891 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 11.5 रुपये की बढ़त के साथ 160.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.45 रुपये की गिरावट के साथ 25.85 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 138000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 296.5 रुपये की गिरावट के साथ 53 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 249000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 7892.5 रुपये की गिरावट के साथ 12623 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 24.66 रुपये की गिरावट के साथ 73.1 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 75 पैसे की नरमी के साथ 9.7 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 9.5 रुपये की गिरावट के साथ 108.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7.15 रुपये की बढ़त के साथ 30.65 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 135000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 276.5 रुपये की बढ़त के साथ 535.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 899 रुपये की बढ़त के साथ 3180 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 28.05 रुपये की बढ़त के साथ 89.72 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 25 पैसे की नरमी के साथ 9.5 रुपये हुआ।

पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए, 04 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विशेष किराये पर विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 04828/04827 बांद्रा टर्मिनस – भगत की कोठी स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस–भगत की कोठी स्पेशल को 01 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 31 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

2. ट्रेन संख्या 09622/09621 बांद्रा टर्मिनस – अजमेर स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस–अजमेर स्पेशल को 26 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09621 अजमेर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 25 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

3. ट्रेन संख्या 09057/09058 उधना – मंगलुरु स्पेशल (द्विसाप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09057 उधना–मंगलुरु स्पेशल को 28 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09058 मंगलुरु–उधना स्पेशल को 29 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

4. ट्रेन संख्या 09059/09060 उधना – खुरदा रोड स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09059 उधना–खुरदा रोड स्पेशल को 25 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09060 खुरदा रोड–उधना स्पेशल को 27 फरवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 04828 एवं 09622 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 01 जनवरी, 2026 से जबकि, ट्रेन संख्या 09057 एवं 09059 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 02 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सरकार ने निर्यातकों के लिए संरचित वैश्विक बाज़ार पहुंच को आसान बनाने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन के तहत मार्केट एक्सेस सपोर्ट (एमएएस) योजना शुरू की - फियो अध्यक्ष

नई दिल्ली, 31 दिसंबर 2025- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन मिशन (एपीएम) के तहत मार्केट एक्सेस सपोर्ट (एमएएस) योजना शुरू करने का स्वागत किया है और इसे भारत के वैश्विक निर्यात पदचिह्न , खासकर एमएसएमई , पहली बार निर्यात करने वालों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की फर्मों को मजबूत करने के लिए एक समय पर और रणनीतिक कदम बताया है।

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना भारत की निर्यात संवर्धन रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। पूर्वानुमानित, अच्छी तरह से नियोजित और परिणाम-उन्मुख बाज़ार पहुंच गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार ने निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई की एक लंबे समय से चली आ रही ज़रूरत को पूरा किया है, जिन्हें अक्सर विदेशी बाजारों तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

एमएएस योजना, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर, 2025 को मंज़ूरी दी थी, निर्यात संवर्धन मिशन की निर्यात दिशा उप-योजना के तहत लागू किया जा रहा है। यह मिशन वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशों में भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और उद्योग संघों के साथ घनिष्ठ समन्वय में संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है।

एमएएस के तहत, सरकार खरीदार-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) , अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों, भारत में आयोजित मेगा रिवर्स बायर-सेलर मीट (आरबीएसएम) और प्राथमिकता वाले और उभरते बाजारों में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के लिए संरचित वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य परिणाम-उन्मुख बाज़ार पहुंच पहलों के माध्यम से खरीदारों से संपर्क में सुधार करना और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना है।

श्री रल्हन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का तीन से पांच साल का अग्रिम कैलेंडर प्रदान करने से निर्यातकों और व्यापार निकायों के लिए योजना की निश्चितता में काफी सुधार होगा। एमएसएमई की न्यूनतम 35 प्रतिशत भागीदारी अनिवार्य करना और नए भौगोलिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, भारत के निर्यात विकास को व्यापक बनाने और विविधीकरण को बढ़ावा देने में बहुत मददगार होगा।

एमएएस ढांचा कार्यक्रम स्तर की वित्तीय सहायता सीमाओं और लागत-साझाकरण अनुपातों को भी तर्कसंगत बनाता है, जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और बाजारों के लिए तरजीही सहायता दी जाती है। पिछले साल 75 लाख रूपये तक के निर्यात टर्नओवर वाले छोटे निर्यातकों को आंशिक हवाई किराए में मदद मिलेगी, जिससे ग्लोबल इवेंट्स में नए और छोटे निर्यातकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

इस स्कीम के डिजिटल होने पर ज़ोर देते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि trade.gov.in पोर्टल के ज़रिए प्रक्रियाओं की समग्र डिजिटाइज़ेशन पारदर्शिता, आसानी से पहुंच और तेज़ी से अप्रूवल सुनिश्चित करेगा। अनिवार्य ऑनलाइन फीडबैक, लीड ट्रैकिंग और परिणाम मापने वाले टूल बाज़ार पहुंच के उपायों को असल बिज़नेस नतीजों के साथ जोड़ने में मदद करेंगे।

फियो ने खासकर टेक्नोलॉजी-इंटेंसिव और सनराइज़ सेक्टर के लिए प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन सपोर्ट शुरू करने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया और मार्केट इंटेलिजेंस और निर्यातक फॉलो-अप के लिए एडवांस्ड डिजिटल टूल को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का भी स्वागत किया। श्री रल्हन ने कहा कि एमएएस में मज़बूत खरीदार जुड़ाव, डेटा-संचालित पॉलिसी फीडबैक और भारतीय निर्यातकों को ग्लोबल वैल्यू चेन में गहराई से जोड़ने के ज़रिए भारत के निर्यात इकोसिस्टम की नींव बनने की क्षमता है।

फियो ने एमएएस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और निर्यात करने वाले समुदाय के लिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे सुनिश्चित करने के लिए सरकार और सभी हितधारक के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।